

शुरुआत. उत्कृष्ट विद्यालयों का उद्घाटन, नामांकन प्रक्रिया शुरू

इसी साल 50 हजार शिक्षकों की होगी नियुक्ति : मुख्यमंत्री

प्रमुख संवाददाता, रांची

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी है. कई तरह की बाधाओं की वजह से नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पायी. अब समस्याओं का समाधान कर लिया गया है. इस माह के अंत तक पहले चरण में राज्य में 25,996 शिक्षकों की नियुक्ति की जायेगी. वहीं दूसरे चरण में इस वर्ष के अंत तक और 24,004 शिक्षक नियुक्त किये जायेंगे. श्री सोरेन ने मंगलवार को जगन्नाथपुर स्थित ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव उच्च विद्यालय के साथ राज्य के 80 उत्कृष्ट विद्यालयों का उद्घाटन के अवसर पर यह बातें कही. इसके बाद उन्होंने उत्कृष्ट विद्यालयों में नामांकन शुरू करने की घोषणा की. उन्होंने कहा कि सभी उत्कृष्ट विद्यालय को सीबीएसई से मान्यता मिली है. यहां पर अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई होगी. श्री सोरेन ने कहा कि दूसरे चरण में प्रखंड स्तर पर 325 व तीसरे चरण में पंचायत स्तर पर 4036 उत्कृष्ट विद्यालय खोले जायेंगे. श्री सोरेन ने कहा कि बेहतर प्रदर्शन करनेवाले स्कूलों, शिक्षकों व विद्यार्थियों को सरकार पुरस्कृत करेगी.

पढ़ाई के लिए बच्चे नहीं करें पैसे की चिंता : मुख्यमंत्री ने कहा कि विदेशों में पढ़ने के लिए सरकार की ओर से शत प्रतिशत स्कॉलरशिप दी जा रही है. बच्चियों के लिए सावित्री बाई



जगन्नाथपुर स्थित ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव उच्च विद्यालय में कार्यक्रम में दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने राज्य के 80 उत्कृष्ट विद्यालयों का उद्घाटन किया.

25,996

शिक्षकों की होगी
नियुक्ति पहले चरण में
इस माह के अंत तक

24,004

शिक्षकों की नियुक्ति
दूसरे चरण में दिसंबर
तक करेगी सरकार

झारखंड जैसे राज्य में यह काम वर्षों पहले होना चाहिए था, पांच हजार स्कूलों को उत्कृष्ट विद्यालय बनाने की हो रही है तैयारी

श्री सोरेन ने कहा कि शिक्षा एक ऐसा शस्त्र है, जिसके माध्यम से सभी चीजें हासिल की जा सकती हैं. परंतु झारखंड जैसे राज्य में जो काम बहुत पहले होना चाहिए था, वह बहुत विलंब से शुरू हुआ है. अभी राज्य में 35 हजार से ज्यादा सरकारी स्कूल हैं. हम अभी

चार से पांच हजार विद्यालय को उत्कृष्ट बनाने का काम कर रहे हैं. वर्षों से इन स्कूलों में जैसी पढ़ाई की व्यवस्था रही, वह चिंताजनक है. सरकार ने पुरानी व्यवस्था को दुरुस्त करते हुए कदम बढ़ाया है, ताकि प्रतिस्पर्धा की दौड़ में राज्य के गरीब, आदिवासी, पिछड़े बच्चों

को बेहतर शिक्षा दी जा सके. उन्होंने कहा कि प्राइवेट स्कूल के शिक्षकों को सरकारी स्कूलों के शिक्षकों जितना वेतन नहीं मिलता है. हमें प्राइवेट स्कूलों के प्रबंधन को समझने की आवश्यकता है. शिक्षा को सरकारी मकड़जाल से दूर रखने की जरूरत है.

फुले योजना शुरू की गयी है. इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में विकास को लेकर सरकार ने मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना, गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की है, ताकि राज्य के गरीब व

प्रतिभावान बच्चों को दिक्कत नहीं हो. उन्होंने कहा कि बच्चे किसी भी परिस्थिति में पढ़ाई बंद नहीं करें. पढ़ाई के लिए पैसे की चिंता नहीं करें. राज्य सरकार उनके खर्च का वहन

करेगी. उच्च शिक्षा की तैयारी का भी खर्च सरकार उठायेगी. उन्होंने कहा कि जेडई की परीक्षा में कस्तूरबा गांधी की बच्चियों में शानदार प्रदर्शन किया है. मैं खुद उनसे मुलाकात करूंगा.